रजिस्टर्ड न० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 19 सितम्बर, 1987/28 भाद्रपद, 1909

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 15th September, 1987

No. 1-32/87-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, The Himachal Pradesh

Appropriation (No. 4) Bill, 1987 (Bill No. 19 of 1987) having been introduced on the 15th September, 1987 in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

Sd/-
Secretary.

1987 का विधेयक संख्यांक 19.

हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1987

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से सेवाओं के लिए कतिपय अतिरिक्त धन-राशियों के संदाय को प्राधिकृत करने और उनका विनियोग करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के अड़तीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम ।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 4) अधिनियम, 1987 है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए 36,55,37,543 रुपये की और राशि जारी करना ।

2. हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के तृतीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट से अनधिक अतिरिक्त धन-राशियां, जिनका योग 36,55,37,543 रुपये (छत्तीस करोड़, पचपन लाख, सैंतीस हजार, पांच सौ तैंतालीस रुपये) है, संदत्त और उपयोजित की जाएं जिनका वित्तीय वर्ष 1987-88 की अवधि में अनुसूची के द्वितीय स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवाओं से सम्बन्धित प्रभारों को चुकाने के लिए उपयोग किया जाएगा।

विनियोग।

3. इस अधिनियम द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से संदत्त और उपयोजित किए जाने के लिए प्राधिकृत धन-राशियों का इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि से सम्बन्धित अनुसूची में अभिव्यक्त सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजन किया जाएगा ।

अनुसूची

(धारा 2 और 3 देखें)

1	2		3		
			निम्नलिखित राशियों से अनधिक		
मांग संख्या	सेवाएं एवं प्रयोजन		विधान सभा द्वारा दत्तमत	संचित निधि पर प्रभारित	जोड़
			रुपये	रुपये	रुपये
3	न्याय प्रशासन	(राजस्व)	8,62,000	—	8,62,000
4	सामान्य प्रशासन	(राजस्व)	88,57,000	—	88,57,000
5	भू-राजस्व	(राजस्व)	7,03,70,000	—	7,03,70,000
7	पुलिस और सम्बद्ध संगठन	(राजस्व)	4,75,000	—	4,75,000
8	शिक्षा, खेलें तथा कला और	(राजस्व)	1,36,50,000	—	1,36,50,000
	संस्कृति	(पूंजी)	7,50,000	—	7,50,000
9	चिकित्सा और परिवार	(राजस्व)	—	1,82,728	1,82,728
	कल्याण	(पूंजी)	—	1,000	1,000
10	लोक निर्माण	(राजस्व)	23,57,000	—	23,57,000
		(पूंजी)	34,05,000	2,97,435	37,02,435
11	कृषि	(राजस्व)	6,18,50,000	3,350	6,18,53,350
		(पूंजी)	20,00,000	—	20,00,000
12	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	(राजस्व)	33,00,000	—	33,00,000
		(पूंजी)	—	41,717	41,717
16	वन और वन्य जीवन	(राजस्व)	55,50,000	1,39,153	56,89,153
		(पूंजी)	10,00,000	—	10,00,000
17	सड़कें और पुल	(राजस्व)	5,19,69,000	4,50,000	5,24,19,000
		(पूंजी)	1,56,45,240	45,50,000	2,01,95,240
18	आपूर्ति, उद्योग और खनिज	(राजस्व)	26,300	5,258	31,558
19	सामाजिक सुरक्षा, कल्याण	(राजस्व)	1,11,21,000	—	1,11,21,000
	(पोषाहार सहित)	(पूंजी)	11,04,000	—	11,04,000
20	ग्रामीण विकास	(राजस्व)	5,00,70,000	20,000	5,00,90,000
23	जल और विद्युत विकास	(राजस्व)	18,00,000	—	18,00,000
27	श्रम और रोजगार	(पूंजी)	—	2,03,975	2,03,975
28	जल आपूर्ति, सफाई, आवास	(राजस्व)	56,57,000	—	56,57,000
	और नगर विकास	(पूंजी)	3,22,05,000	11,62,323	3,33,67,323
29	वित्त	(राजस्व)	—	15,614	15,614
		(पूंजी)	50,00,000	—	50,00,000

1	2		3		
			रुपये	रुपये	रुपये
31	जन-जातीय विकास	(राजस्व)	84,70,400	21,050	84,91,450
		(पूंजी)	9,50,000	—	9,50,000
		जोड़	35,84,43,940	70,93,603	36,55,37,543
		(राजस्व)	29,63,84,700	8,37,153	29,72,21,853
		(पूंजी)	6,20,59,240	62,56,450	6,83,15,690

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के साथ पठित अनुच्छेद 204 के खण्ड (1) के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से वित्तीय वर्ष 1987-88 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुमानित व्ययों के सम्बन्ध में संचित निधि पर प्रभारित व्ययों और विधान सभा द्वारा यथा दत्तमत अन्य व्ययों को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से अपेक्षित अतिरिक्त धन के विनियोजन का उपबन्ध करने के लिए पुरःस्थापित है ।

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री

शिमला :
15 सितम्बर, 1987.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें

[वित्त विभाग फाइल संख्या फिन-ए-सी(2) 20/87]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1987 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं ।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Viniyog (Sankhya 4) Vidheyak*, 1987(1987 *ka Vidheyak Sankhyank* 19) *as required under clause* (3) *of Article* 348 *of the Constitution of India*].

Bill No. 19 of 1987.

THE HIMACHAL PRADESH APPROPRIATION (NO. 4) BILL, 1987

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the services for the financial year ending on the 31*st day of March*, 1988.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-eighth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Act, 1987. Short title.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of Rs. 36,55,37,543 (Thirty six crores, fifty-five lakhs, thirty-seven thousand, five hundred and forty three rupees) towards defraying the charges which will come in course of payment during the financial year 1987-88 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule. Issue of a further sum of Rs. 36,55,37,543 out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh for the financial year 1987-88.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh by this Act shall be further appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the period specified under section 2 of this Act. Appropriation.

THE SCHEDULE

(*See* sections 2 and 3)

1	2		3		
			Sums not exceeding		
Demand No.	Services and purposes		Voted by the Legislative Assembly	*Charged* on the Consolidated Fund	Total
			Rs	Rs.	Rs.
3	Administration of Justice	(Revenue)	8,62,000	—	8,62,000
4	General Administration	(Revenue)	88,57,000	—	88,57,000
5	Land Revenue	(Revenue)	7,03,70,000	—	7,03,70,000
7	Police and Allied Organisations	(Revenue)	4,75,000	—	4,75,000
8	Education, Sports and Arts and Culture	(Revenue)	1,36,50,000	—	1,36,50,000
		(Capital)	7,50,000	—	7,50,000
9	Health and Family Welfare	(Revenue)	—	1,82,728	1,82,728
		(Capital)	—	1,000	1,000
10	Public Works	(Revenue)	23,57,000	—	23,57,000
		(Capital)	34,05,000	2,97,435	37,02,435
11	Agriculture	(Revenue)	6,18,50,000	3,350	6,18,53,350
		(Capital)	20,00,000	—	20,00,000
12	Irrigation and Flood Control	(Revenue)	33,00,0 0	—	33,00,000
		(Capital)	—	41,717	41,717
16	Forest and Wild Life	(Revenue)	55,50,000	1,39,153	56,89,153
		(Capital)	10,00,000	—	10,00,000
17	Roads and Bridges	(Revenue)	5,19,69,000	4,50,000	5,24,19,000
		(Capital)	1,56,45,240	45,50,000	2,01,95,240
18	Supplies, Industries and Minerals	(Revenue)	26,300	5,258	31,558
19	Social Security, Welfare (including nutrition)	(Revenue)	1,11,21,000	—	1,11,21,000
		(Capital)	11,04,000	—	11,04,000
20	Rural Development	(Revenue)	5,00,70,000	20,000	5,00,90,000
23	Water and Power Development	(Revenue)	18,00,000	—	18,00,000
27	Labour and Employment	(Capital)	—	2,03,975	2,03,975
28	Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development	(Revenue)	56,57,000	—	56,57,000
		(Capital)	3,22,05,000	11,62,323	3,33,67,323
29	Finance	(Revenue)	—	15,614	15,614
		(Capital)	50,00,000	—	50,00,000
31	Tribal Development	(Revenue)	84,70,400	21,050	84,91,450
		(Capital)	9,50,000	—	9,50,000
	Total ...		35,84,43,940	70,93,603	36,55,37,543
		(Revenue)	29,63,84,700	8,37,153	29,72,21,853
		(Capital)	6,20,59,240	62,56,450	6,83,15,690

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

This Bill is introduced in pursuance of clause (1) of Article 204 read with Article 205 of the Constitution of India to provide for the appropriation from and out of the Consolidated Fund of the State of Himachal Pradesh of the moneys further required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and other expenditure as voted by the Legislative Assembly in respect of the estimated expenditure of the Government of Himachal Pradesh for the financial year 1987-88.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

SHIMLA :
The 15th September, 1987.

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

[Finance Department File No. Fin. A-C(2) 20/87]

The Governor, Himachal Pradesh, having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Appropriation (No. 4) Bill, 1987, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the said Bill by the Legislative Assembly.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।